

National seminar on human rights

<https://thelivenagpur.com/2022/09/07/national-seminar-on-human-rights/>

The Maharashtra National Law University, Nagpur is hosting a National Seminar on Human Rights on the 8th and 9th of September, 2022 under the aegis of the National Human Rights Commission.

The NHRC is a statutory organization that embodies India's concern for the promotion and protection of human rights.

The seminar, centered around the topic "Manav Adhikaron ki Amrit Uplabdhayan", will include three academic sessions with key addresses from note-worthy personalities, such as Rajiv Jain, the former Director of IB and Sanjay Kumar, the Under Secretary of National Human Rights Commission. Students shall also play an active role in the seminar.

The conference aims to examine the relationship between Literature Society and Human Rights in a session presided by K Shrinivas Rao, the Secretary of Sahitya Academy.

The second session centers around Media's Role in Promotion of Human Rights, this session includes lectures from prominent journalists such as Sudhanshu Ranjan. The third session will be on the Commitment of Police towards the Protection of Human Rights which will include addresses from Joel Joseph Denga and Vikas Mishra IPS.

Need to ponder why some states have low MMR compared to others: NHRC chief

<https://www.eastmojo.com/national/2022/09/08/need-to-ponder-why-some-states-have-low-mmr-compared-to-others-nhrc-chief/>

NHRC chairperson justice (retd) Arun Kumar Mishra has flagged the issue of imbalance in sex ratio in the country and also asked to ponder why some states have low maternal mortality rate (MMR) compared to others.

He said this while chairing a meeting on 'Women's health, survival and nutritional status in India: Challenges and Way Forward' hosted by the National Human Rights Commission on September 5, officials said on Tuesday.

Chairing it, justice Mishra said there are enabling laws and policy frameworks towards ensuring better healthcare for women as well as their empowerment.

However, these require to be implemented in the right earnest. The imbalance in the sex ratio between male and female child remains a "point of concern", he was quoted as saying in a statement issued by the NHRC.

He said it is perhaps due to the mindset, which is causing this "disparity between the male and female child despite that the girls legally have an equal share in the inheritance of parental property".

"Society as a whole needs to ponder over it," the NHRC chief said.

Justice Mishra also said that the MMR has comparatively declined in the country, but it continues to remain high. He emphasised that it is to be "pondered as to why some states have low MMR compared to others".

The NHRC chairperson said "the intra-state differences in MMR reflect the existing inequality in access to factors that determined women's health, including healthcare services".

Earlier, NHRC Secretary General, D K Singh said the aim of the meeting is to have inputs from different stakeholders including the Union ministries, which have been working for women empowerment, as part of the Centre's policies, and find out the gaps in the policies and their implementation, the statement said.

प्रदूषित पानी परेशानी का सबब, मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज

<https://jantaserishta.com/local/uttar-pradesh/polluted-water-causes-trouble-complaint-filed-in-human-rights-commission-1545547>

लम्बे वक्त से गांव में नाले के जरिए बह रहा फैक्टरियों का प्रदूषित पानी ग्रामवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसकी शिकायत फरीदपुर के गांव नौगवां की ओर से मानव अधिकार आयोग में दर्ज कराई गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव ने मामले को मानवाधिकार का हनन मानते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली में दर्ज करा दिया है। जल्द ही फैक्ट्री संचालकों को नोटिस जारी हो जाएंगे। निस्तारण न होने पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में भी मामला दर्ज कराने जा रहे हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय में भी रिट के जरिए जाने की तैयारी है। एडवोकेट गजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि नाला टीपी नगर से होता हुआ आता है और ग्राम नौगवां के रेलवे के पुल के नीचे से गुजरता है। इस नाले में रजऊ परसपुर की फैक्टरियों का प्रदूषित पानी छोड़ा जाता है। इस नाले का पानी विषाक्त पदार्थों से युक्त है। यह पानी इतना दूषित व हानिकारक है कि इसमें यदि कोई मवेशी भी चला जाए तो उसे त्वचा संक्रमण हो जाता है। इस प्रदूषण की वजह से गांव के हैंडपंप से आने वाला पानी भी दूषित हो चुका है तथा पीने के जल में भी हानिकारक प्रदूषक मौजूद है। इससे पूरे गांव में अनेक लोगों को प्रदूषण जनित बीमारियां हो चुकी हैं तथा भविष्य में भी कोई बड़ी संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा है। इसकी शिकायत ग्रामवासियों ने कई बार जनसुनवाई पोर्टल पर तथा पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी फरीदपुर को सूचित किया लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हुई और न ही कोई अधिकारी मौके पर जांच को पहुंचा है।

बरेली: प्रदूषित पानी परेशानी का सबब, मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज

<https://amritvichar.com/bareilly-polluted-water-causes-trouble-complaint-filed-in-human-rights-commission/>

लम्बे वक्त से गांव में नाले के जरिए बह रहा फैक्टरियों का प्रदूषित पानी ग्रामवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसकी शिकायत फरीदपुर के गांव नौगवां की ओर से मानव अधिकार आयोग में दर्ज कराई गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव ने मामले को मानवाधिकार का हनन मानते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली में दर्ज करा दिया है। जल्द ही फैक्ट्री संचालकों को नोटिस जारी हो जाएंगे। निस्तारण न होने पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में भी मामला दर्ज कराने जा रहे हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय में भी रिट के जरिए जाने की तैयारी है।

एडवोकेट गजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि नाला टीपी नगर से होता हुआ आता है और ग्राम नौगवां के रेलवे के पुल के नीचे से गुजरता है। इस नाले में रजऊ परसपुर की फैक्टरियों का प्रदूषित पानी छोड़ा जाता है। इस नाले का पानी विषाक्त पदार्थों से युक्त है। यह पानी इतना दूषित व हानिकारक है कि इसमें यदि कोई मवेशी भी चला जाए तो उसे त्वचा संक्रमण हो जाता है। इस प्रदूषण की वजह से गांव के हैंडपंप से आने वाला पानी भी दूषित हो चुका है तथा पीने के जल में भी हानिकारक प्रदूषक मौजूद है।

इससे पूरे गांव में अनेक लोगों को प्रदूषण जनित बीमारियां हो चुकी हैं तथा भविष्य में भी कोई बड़ी संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा है। इसकी शिकायत ग्रामवासियों ने कई बार जनसुनवाई पोर्टल पर तथा पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी फरीदपुर को सूचित किया लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हुई और न ही कोई अधिकारी मौके पर जांच को पहुंचा है।